भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–20 जनवरी, 2019

साइकिल यात्रा से शांति संभव नहीं!
मध्य भारत में असली शांति के लिए संसाधनों की कॉरपोरेट लूट बंद करने, कैंपों को बंद कर पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों को वापस भेजने की मांग करें!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ सहित देश भर के आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े तबकों की जनता, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर मीडियाकर्मियों, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार व महिला संगठनों, छात्रों, नवजवानों एवं असली शांति चाहने वाले सभी लोगों से अपील करती है कि वे मध्य भारत में शांति के नाम पर आगामी 22 से 28 फरवरी तक प्रस्तावित जगदलपुर–रायपुर 'शांति साइकिल यात्रा' के आयोजक देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के विश्वसनीय सेवक/एजेंट शुभ्रांशु चौधरी की असलियत को पहचाने एवं उक्त यात्रा का बहिष्कार करें एवं उससे दूर रहें. साथ ही हमारी पार्टी यह आह्वान करती है कि वे मध्य भारत में असली शांति कायम करने के लिए देश के संसाधनों की कॉरपोरेट लूट से संबंधित तमाम एमओयू को रद्द करने, संघर्ष इलाकों से कैंपों को बंद करके पुलिस, अर्ध–सैनिक व कमांडो बलों को वापस भेजने तथा डीआरजी, बस्तर बटालियन, ब्लैक पैंथर्स आदि हत्यारे कमांडो बलों को रद्द करने की सरकारों से जोरदार मांग करें.

यह जगजाहिर है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी देश के क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करके सार्वजनिक संपत्ति एवं संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने के तमाम एमओयू पर अमल को यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए ही मई, 2017 से केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा बहुआयामी 'समाधान' दमन योजना लागू की जा रही है. उसी के तहत कॉरपेट सेक्युरिटी का विस्तार करते हुए लगातार नए कैंप बैठाए जा रहे हैं. बड़े पैमाने पर पुलिस, अर्ध–सैनिक, कमांडो बल तैनात किए जा रहे हैं. गांवों पर हमलें तेज किए जा रहे हैं.

यहां यह समझना आवश्यक है कि शुभ्रांशु की अगुआई में प्रस्तावित शांति साइकिल यात्रा दरअसल इसी 'समाधान' का एक कुटिल व षड्यंत्रकारी पहलू है. समाधान के बर्बर दमन पर परदा डालने की कोशिश का हिस्सा है. यह खनन व औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकारों के साथ एमओयू करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा उनके फायदे के लिए प्रायोजित कार्यक्रम है. साम्राज्यवादी हित पोषक चिंतक समूह(थिंक टैंक) एवं एमआईटी (मेसाच्यूसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) जैसे कॉरपोरेट उच्च प्रोद्योगिकी संस्थानों से उपजे सीजी नेट, स्वरा जैसे कार्यक्रमों का संचालन करते हुए शुभ्रांशु संवाद के नाम पर आदिवासी जनता, बुद्धिजीवियों व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को विस्थापन विरोधी व क्रांतिकारी आंदोलनों से दूर करने/भटकाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 15 सालों के दौरान जारी भाजपा सरकार की जनविरोधी व दमनकारी नीतियों का कुछ हद तक विरोध करते हुए एवं राज्य की जनता में व्याप्त भाजपा विरोधी माहौल का उपयोग करके दिसंबर, 2019 में सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार ने भाजपा के ही ढर्रे पर चलते हुए नए कैंप बैठा रही है. हाल ही में कांकेर जिले के कोइलीबेडा के डुट्टा एवं छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के सरहदी पानावारा में एक–एक नया कैंप बैठाया है. चुनाव के पहले जो फासीवादी दमन चल रहा था, वह चुनावों के दौरान एवं नई सरकार के गठन के बाद भी बेरोकटोक जारी है. हर हमेशा गश्त अभियान, गांवों पर हमलें, गिरफ्तारियां, मुठभेड़ें निर्बाध गति से जारी ही हैं. कांग्रेस की नई सरकार ने खुलेआम ऐलान किया कि माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस यथावत जारी रहेंगे. नए मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि बस्तर में तैनात अर्ध सैनिक बलों की 70 बटालियन फोर्स नहीं हटायी जाएगी.

ऐसे हालात में शांति साइकिल यात्रा के आयोजकों जिनमें सीपीआई का जन संगठन आदिवासी महासभा भी शामिल है, की ओर से सभी पक्षों से हिंसा त्यागकर बातचीत द्वारा समाधान खोजने की अपील करने का मतलब है, सरकार एवं हमारी पार्टी–दोनों को एक समान देखना जोकि हास्यास्पद ही नहीं, वाहियात भी है. सच तो यह है कि सरकारें स्वयं अशांति व हिंसा फैला रही हैं. हिंसा के बगैर शोषक–शासकों का एक दिन भी नहीं गुजरता है. सशत्र बलों की ताकत के बलबूते ही अपनी सत्ता व लूट को जारी रखे हुए हैं. पिछले साल आयोजित शांति यात्रा, डायलाग–एक हो या आगामी फरवरी में प्रस्तावित शांति साइकिल यात्रा व डायलाग–दो हो, यहां असली समस्या शांति, अहिंसा की नहीं है. समस्या तो वर्ग हितों की है. एक ओर सरकारें देशी, विदेशी कॉरपोरेट

कंपनियों को सशस्त्र ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर कौड़ियों के भाव सार्वजनिक संपत्ति, जमीन, पानी, खनिज संसाधन उपलब्ध कराना चाहती हैं जबकि दूसरी ओर माओवादी पार्टी अनिवार्य रूप से जवाबी प्रतिहिंसा के जरिए उन पर जनता के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहती है. शुभ्रांशु जैसे 'शांति यात्राओं के आयोजक' सरकारी हिंसा और माओवादियों की प्रतिहिंसा को बराबर करते हुए शांति के नाम पर आखिर जनता को अपनी सेना व हथियारबंद ताकत से वंचित करना चाहते हैं, कॉरपोरेट लूट का शिकार बनाना चाहते हैं. यही असल बात है. प्रस्तावित शांति साइकिल यात्रा के लिए जारी अपील में अंकित आदिवासी सामाजिक संगठनों – छग सर्व आदिवासी समाज, अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा, कोया कुटुम, धुर्वा समाज, बस्तरिया समाज, भतरा समाज, गोंडवाना राज गोंड समिति व शबरी गांधी आश्रम सहित उन सभी सही अहिंसावादियों व शांति चाहने वालों जो जाने–अनजाने में शांति साइकिल यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, से हमारी अपील है कि वे शांति साइकिल यात्रा की असलियत को समझकर सही राजनीतिक दशा एवं दिशा अपनाते हुए संसाधनों की लूट व उसके लिए जारी सरकारी हिंसा के खिलाफ यानी 'समाधान' हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करें न कि माओवादियों से शांति की अपील. क्योंकि हमारी पार्टी उत्पीड़ित जनता की असली शांति के लिए लड़ रही है.

यहां यह बताना लाजिमी होगा कि हमारी पार्टी जनता के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है. उसके असली विकास के लिए, उनके निर्मम शोषण के खिलाफ लड़ रही है. उन पर जारी हिंसा को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से जवाबी हिंसा करने बाध्य है. दरअसल हमारी पार्टी उत्पीड़ित–शोषित जनता की जनवादी राज्यसत्ता के लिए लड़ रही है. दंडकारण्य में उदीयमान जन राज्यसत्ता के संगठन – क्रांतिकारी जन कमेटियों जिन्हें शोषक–शासक वर्ग नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, को बनाए व बचाए रखने, उन्हें मजबूत करने व उनका विस्तार करने के लिए हमारी पार्टी जनता की सक्रिय भागीदारी से जनयुद्ध लड़ रही है.

फिर भी हमारी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि अनुकूल माहौल में जनता एवं जन आंदोलनों के हित में वह जनता की तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर शासक वर्गों के साथ वार्ता के लिए तैयार है. लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई भी जनवादी तरीके से काम कर सकता हो.

संसाधनों की लूट संबंधी सारे एमओयू को रद्द करने, सशस्त्र बलों को वापस भेजने जैसे असली व बुनियादी मुद्दों पर शांति साइकिल यात्रा के आयोजक चुप्पी साधे हुए हैं. इनके अलावा कई मांगों को हल्के ढंग से पेश कर रहे हैं. क्योंकि उनका मकसद जनता की मूलभूत समस्याओं का हल नहीं बल्कि माओवादियों के खिलाफ माहौल बनाना मात्र है.

जेलों में न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता–नेता बल्कि हजारों आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता बरसों से बंद हैं. उनके लिए काम करने वाले 'जगलग' (जगदलपुर लीगल एड्ड ग्रुप) के वकीलों को पिछली भाजपा सरकार के संरक्षण में 'अग्नि' के गुंडों ने बस्तर से भगाया था. 2012 में बनी निर्मला बुच समिति के 6 साल के कार्यकाल की नाकामी के बाद जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के नाम पर अभी नए मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने एक और कमेटी बनायी. अब कमेटियों के गठन की मांग नहीं, माओवादी मामलों के सभी जेलबंदियों की तुरंत व निशर्त रिहाई की आवश्यकता है.

उतना ही नहीं, देश के विभिन्न इलाकों के सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, प्रोफेसरों, वकीलों को बस्तर से बाहर कर दिया गया था या उन पर कइयों थानों में झूठे मुकदमें दर्ज किए गए हैं. उन्हें वापस लेकर सभी को स्वेच्छा से काम करने देने की मांग करने की जरूरत है.

5वीं अनुसूची द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों जैसे पेसा, ग्राम सभाओं के अधिकारों तथा वनाधिकार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अवाम को विस्थापित करने वाली खनन, बांध, औद्योगिक, रेल लाइन, सड़क व अभयारण्य परियोजनाओं पर काम जारी है. गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़प कर पुलिस कैंप लगाए जा रहे हैं. पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए नरसंहारों, झूठी मुठभेड़ों व महिलाओं के सामूहिक बलात्कार व हत्याओं के मामलों में न्यायिक जांच का कोई ऐलान तक नहीं हुआ है.

उपरोक्त तमाम मामलों पर मौन साधकर सिर्फ साइकिल यात्रा करना या माओवादियों से शांति/शांति वार्ता की अपील करना न सिर्फ बेमानी है बल्कि आदिवासी जनता के साथ दगाबाजी ही है. यह पूरी कवायद 'समाधान' के साजिशाना हमले का हिस्सा मात्र है. इसे समझें व नाकाम करें.

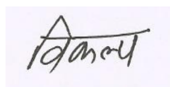

(विकल्प)

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)